मुझे चाहिए कुछ बोल

मुझे चाहिएं कुछ बोल
जिनका एक गीत बन सके...

छीन लो मुझसे यह भीड़ की टें-टें
जला दो मुझे मेरी कविताओं की धूनी पर
मेरी खोपड़ी पर बेशक खनकाएं
शासन का काला डंडा
लेकिन मुझे दे दें कुछ बोल
जिनका एक गीत बन सके...

मुझे नहीं चाहिएं सायानी के डायलॉग
सम्हालें आनंद बख्शी, आप जानें लक्ष्मीकांत
मुझे क्या करना है इंदिरा का भाषण
मुझे तो चाहिएं कुछ बोल
जिनका एक गीत बन सके...

मेरे मुंह में ठूंस दें यमल जट्ट की तूंबी
मेरे माथे पर घसीट दें टैगोर का नेशनल एंथम
मेरे सीने पर चिपका दें गुलशन नंदा के नावेल

मुझे क्यों पढना है जफरनामा
गर मुझे मिल जाएं कुछ बोल
जिनका एक गीत बन सकें...
मेरी पीठ पर लाद दें वाजपेयी का बोझिल बदन
मेरी गर्दन में डाल दें हेमंत बसु की लाश
मेरी...में दे दें लाला जगतनारायण का सिर
चलो, मैं माओ का नाम भी नहीं लेता
लेकिन मुझे दें तो सही कुछ बोल
जिनका एक गीत बन सके...

मुझे पेन में स्याही न भरने दें
मैं अपनी 'लौह कथा' भी जला देता हूं
मैं 'चंदन' से भी कट्टी कर लेता हूं
गर मुझे दे दें कुछ बोल
जिनका एक गीत बन सके...

यह गीत मुझे उन गूंगों को देना है
जिन्हें गीतों की कद्र है
लेकिन जिनका आपके हिसाब से गाना नहीं बनता
गर आपके पास नहीं है कोई बोल, कोई गीत
मुझे बकने दें मैं जो बकता हूं।

पाश की कविता

चिकित्सा का दिखावा:मरीज को मौत का बुलावा

पेज एक का शेष

अस्पताल आ जाते हैं। दूसरा, जिसमें कस्बों के छोटे बड़े हैल्थ सेंटर आते हैं; इन पर 724 करोड़ खर्च करती है। शेष मलेरिया आयुर्वेद, ईएसआई आदि पर खर्च किया जाता है। यह इसलिये रखा गया है कि ग्रामीणों को बहकाया जा सके कि देखो सरकार उन पर कितना खर्च कर रही है। लेकिन सारे ग्रामीण इस कड़वी सच्चाई से हर रोज दो-चार होते हैं। न तो किसी सेंटर पर कभी कोई डॉक्टर आता है और न ही कोई अन्य स्टाफ़। वैसे भी इन सेंटरों पर डॉक्टरों के लिये करने कराने को कुछ खास होता भी नहीं है क्योंकि इन में किसी भी प्रकार का आवश्यक साजो-सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता।

इन सेंटरों पर मरीज तो खूब आते हैं लेकिन इलाज न मिल पाने की वजह से ये लोग शहरी अस्पतालों की ओर लपकते हैं। शहरों में सरकारी नहीं तो प्राइवेट में तो इलाज, महंगा ही सही मिल तो जाता है। इन सेंटरों की खास बात यह है कि यहां तैनात डॉक्टर ड्यूटी पर न जाकर अपने और धंधे करते हैं। पुराना एवं विशेषज्ञ डॉक्टर है तो कहीं बैठ कर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा और नया लड़का है तो वह पीजी (स्नातकोत्तर) में घुसने की तैयारी में जुटा रहेगा। सरकार दोनों ही मामलों में मोटी तनख्वाहें इन डॉक्टरों को देती रहती है। लेकिन यह घोटाला होता ज़िले के सीएमओ की मिलीभगत से ही है। इस घोटाले में सीएमओ व अन्य अधिकारियों का बाकायदा हिस्सा रहता है।

ईएसआई निगम से स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जो 700-800 करोड़ हरियाणा सरकार वसूल सकती है, उस ओर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। ईएसआई नियमों के अनुसार यदि सरकार चिकित्सा सुविधायें अपनी 75 लाख आबादी को उपलब्ध कराना चाहे तो उसे कम से कम 800 करोड़ का बजट बनाना होगा जिसमें से 700 करोड़ ईएसआई निगम वहन करेगा। परन्तु नालायक राज्य सरकार कुल बजट ही 125-145 करोड़ का बनाती है। दूसरी अ ोर ईएसआई निगम राज्य के मज़दूरों से 1000-1200 करोड़ वार्षिक वसूल कर अपने खजाने को भरने में जुटी है।

घोर लापरवाही का शिकार मेवात मेडिकल कॉलेज

भारत सरकार ने करीब 5 वर्ष पूर्व 'अल्पसंख्यक .आयोग फ़ंड से इस कालेज को बनाकर हरियाणा सरकार को दे दिया। लेकिन मुफ़्त में बना बनाया कॉलेज भी इस सरकार को चलाना भारी पड़ रहा है। गत 3 साल से चल रहे इस कॉलेज के अस्पताल में अभी तक 30 से 35 प्रतिशत फैकल्टी (डॉक्टरों) की कमी है। इतना ही नहीं गत 2 वर्षों से यहां कोई एमएस (मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट), जिसने अस्पताल को चलाना होता है, का पद रिक्त पड़ा है। यहां का ड्रीन (डायरेक्टर) संसार चंद गुड़गांव से रोज़ाना आना जाना करते हैं। इनके अलावा और भी कई डॉक्टर गुड़गांव, पलवल एवं मथुरा तक से आना जाना करते हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ़ का भी लगभग यही हॉल है।

उपकरणों एवं डॉक्टरों की कमी के चलते यहां केवल साधारण रोगों का ही इलाज, वह भी थोड़ा बहुत हो पाता है। एक मेडिकल कॉलेज से लोगों को जो आशाऐं एवं अपेक्षाएं होती हैं वे इससे पूरी नहीं हो पा रही हैं।

विदित है कि मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा एवं उपेक्षित क्षेत्र है। शिक्षा के अभाव, जहालत, गरीबी और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में यहां बीमारियों का प्रकोप अत्यधिक रहने से मौतें भी बहुत अधिक होती हैं। मेडिकल कॉलेज खुलने से यहां के बच्चों ने तो कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनना नहीं, उन्हें तो बस केवल चिकित्सा सुविधाओं में बेहतरी की आशा थी जो पूरी नहीं हुई। खट्टर सरकार भी इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र का भला करके राज़ी नहीं। वरना सरकार चाहे तो यहां बढ़िया स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी, मार्केट आदि की सुविधायें प्रदान करके फैकल्टी को यहां आने के लिये आकर्षित कर सकती है। इन्हीं उक्त सुविधाओं के न होने की वजह से कोई यहां रह कर राज़ी नहीं।

सरकारी स्कूलों में मनेगा जन्मदिन

केवल पढ़ाई ही नहीं होगी बाकी सब कुछ होगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा के शिक्षा मन्त्री रामबिलास शर्मा ने गत सप्ताह घोषणा की है कि उनके तमाम सरकारी स्कूलों में लड़कियों का जन्म दिन मनाया जाय ताकि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जुमला साकार हो सके।

सर्वविदित है कि हरियाणा सरकार के स्कूलों में पढाई को छोड़ कर सब कुछ होता है। जन्म दिन मनाने की कसर बाकी थी वह अब मन्त्री जी पूरी कर देंगे। बच्चों को पढाई के बदले मिड-डे-मील दिया जाता है। उसे खाकर बच्चे भले ही बीमार हो जायें लेकिन मील देने का यह धंधा बदस्तूर जारी है, क्योंकि इस धंधे में अच्छा-खासा गोल माल चल रहा है जिससे तमाम सम्बन्धित अधिकारियों व नेताओं को अच्छी-खासी लूट कमाई मिल जाती है।

दलित, पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के बच्चों को पढा-लिखा कर सबल बनाने की बजाय सरकार उन्हें खैरात के रूप में मोटे वजीफ़े बांट रही है। इन वजीफ़ों को पाने के लिये बच्चों को केवल स्कूल रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना होता है। बच्चों को मिलने वाला यह पैसा बच्चों के तो किसी काम आता नहीं, उनका घर खर्च चलाने में जरूर काम आता है। कुछ घरों में इससे राशन-पानी आता है तो अधिकांश लोगों की शराब का खर्च निकल जाता है। मास्टरों का वेतन देने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है, खैरात बांट कर बच्चों सहित समाज को बर्बाद करने को पैसा है। स्कूल में बिजली रहे न रहे, कम्प्यूटर सिखाने वाला हो ना हो परन्तु सैंकड़ों करोड़ के कम्प्यूटर खरीद कर स्कूलों में डम्प करने के लिये सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं क्योंकि सैंकड़ों करोड़ की खरीद पर करोड़ों का कमीशन जो मिलता है। अफ़सरों व नेताओं को केवल अपने कमीशन से मतलब रहता है उसके बाद बेशक वे कम्प्यूटर एवं एजुसेट कबाड़ा बन कर स्कूल के एक-दो कमरे घेरे रहें।

जो सरकार बेटियों को सुरक्षित स्कूलों तक आना-जाना मुहैया नहीं करा सकती वह जन्म दिन मनाने जैसे पाखंड तो कर ही सकती है। आये दिन गुंडागर्दी की शिकार बच्चियों द्वारा स्कूलों का बहिष्कार करने के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासनों से इतर कुछ भी नहीं कर रही। जुमलेबाज़ी एवं भांति-भांति के पाखंड के अलावा यह सरकार और कुछ करने लायक है भी नहीं।

लुढकती पढ़ाई चढ़ती फ़ीस

शेष पेज दो पर

बात अलग है कि इस बजट में सेंधमारी करके सैंकड़ों करोड़ भ्रष्टाचारी हड़प जाते हैं और यदि कोई संजीव चतुर्वेदी उन्हें पकड़ने आये तो (केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री) नड्डा के पेट में भयंकर दर्द हो उठता है।

जनता को बरगलाने के लिये खट्टर सरकार सफ़ाई दे सकती है कि उन्होंने फ़रीदाबाद (नहर पार)में 100 एकड़ ज़मीन में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तथा दूसरा बहादुरगढ के निकट खोलने हेतु शिलान्यास कर दिये हैं। इनके बारे में 'मज़दूर मोर्चा' पूरी विस्तृत रिपोर्ट उसी वक्त प्रकाशित कर चुका है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शिक्षा व्यापारियों की दुकान होंगे। मेडिकल कॉलेज के नाम पर ली गयी सैंकड़ों एकड़ ज़मीन के बड़े भाग पर रीयल एस्टेट का धंधा यानी रिहायशी एवं व्यवसायिक प्लॉट बनाने व बेचने का धंधा किया जायेगा। कहने की जरूरत नहीं इस धंधे में राजनेताओं की भी बराबर की हिस्सेदारी सदैव रहती आई है। इस तरह के धंधेबाज़ों को किसी खट्टर विशेष से कोई लेना-देना नहीं होता, इनके लिये सब बराबर हैं चाहे हुड्डा हो या चौटाला। ये तो पैसा फ़ेंक कर धंधा करने वाले लोग हैं। वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा भी दाना मांझी की नियति के लिये जाना जायेगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,**
2. **प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,**
4. **रैंक, 45 नीलम चौक,**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,**
6. **राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब**